रिपोर्ट जिसकी स्थापना 24 प्रपुंज औषधियों जिनमें एम्पटी हाई गिलेटिन कैपसूल भी शामिल है, के मूल्यों के ढांचे के बारे में, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई थी, परीक्षणाधीन हैं।

न्यायालयों में गवाहों के बयानों को उनकी अपनी भाषा में लिखवाने सम्बन्धी विधान

1120. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश भर में कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिसके अधीन न्यायालयों में गवाहों के बयान, अंग्रेजी में अनुवाद करने की बजाये जैसा कि अब हो रहा है, उनकी अपनी भाषा में ही लिखे जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री निति राज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रुस के तेल विशेषज्ञों की भारत यात्रा

1121. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के तेल विशेषज्ञों ने फरवरी, 1973 में भारत की यात्रा की थी और यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ख) क्या उक्त विशेषज्ञों के आने से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को लाभ हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो उनके आने से क्या लाभ पहुंचे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। उनके आने का उद्देश्य ओ० एन० जी० सी० की तेल अन्वेषण और उत्पादन के लिए विशेषज्ञों की सेवाओं और उपकरणों की सप्लाई के रूप में सोवियत संघ से तकनीकी सहायता की आवश्यकताओं पर बातचीत करना और कठिन क्षेत्रों में गहरी खुदाई पर परामर्श देना था।

(ख) जी हां।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की सेवा दिये जाने के लिए सोवियत संघ की सहमति प्राप्त की गई है। सोवियत शिष्टमण्डल ने यह भी मान लिया है कि उपकरण की ऐसी मदें जो ओ० एन० जी० सी० के विशेष विवरण के अनुसार है और उस देश के प्रतियोगी मूल्यों पर उपलब्ध है समय पर पहुंचाये जायेंगे। दुर्गम क्षेत्रों में गहरी खुदाई पर परामर्श देने के लिए भी रूसी विशेषज्ञ सहमत हो गये हैं।

Financial Assistance for Anti-Sea Erosion Project

1122. SHRI A. K. GOPALAN: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether the Central Flood Control has recommended in its 14th meeting that the pattern of financial assistance for the anti-Sea Erosion Project should be revised to 100 per cent grant by the Central Government;